संपादकीय जागरण

गुरुवार, 31 मई, 2018 : द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण 2 वि. 2075

सरलता सबसे आकर्षक गुण है

# किसानों की आमदनी

**केंद्रीय कृषि** मंत्री राधामोहन सिंह के इस दावे को खारिज नहीं किया जा सकता कि बीते चार सालों में मोदी सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह कहना कठिन है कि उनकी तरह औसत किसान भी उन सब योजनाओं को सफल होते हुए देख रहे हैं जो खेती को लाभदायक बनाने के लिए लागू की गई हैं। निःसंदेह बात तब बनेगी जब किसानों को यह भरोसा हो जाए कि अगले कुछ वर्षों में उनकी आय वास्तव में दोगुनी होने जा रही है। इससे इन्कार नहीं कि मोदी सरकार बार-बार यह कह रही है कि वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध है और इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की हालत में उतनी तेजी से सुधार होता हुआ नहीं दिखता कि यह माना जाने लगे कि अगले चार सालों में खेती मुनाफे का सौदा बन जाएगी। चूंकि अगले आम चुनाव में एक साल की ही देर है इसलिए कृषि मंत्रालय को इस पर ध्यान देना होगा कि किसानों की बेचैनी समाप्त हो। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि किसानों को उनकी कृषि उपज का लागत से इतना अधिक मूल्य मिले कि खेती घाटे का सौदा न रहे और किसान अपना जीवन-यापन अच्छी तरह कर सकें।

यह अच्छी बात है कि कृषि मंत्री ने यह रेखांकित किया कि सरकार दो दर्जन से अधिक फसलों का समर्थन मूल्य उनकी लागत का डेढ़ गुना देने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका है कि आखिर लागत मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? लागत मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया जो भी हो, वह किसानों के हितों की पूर्ति करने और उन्हें संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए। इस मामले में कृषि मंत्रालय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि केवल उचित समर्थन मूल्य की घोषणा ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि कृषि उपज घोषित समर्थन मूल्य के आधार पर ही खरीदी जाए। कृषि मंत्री और उनका मंत्रालय इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि कई बार संतोषजनक समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन उस मूल्य पर कृषि उपज की बिक्री इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि सरकारी एजेंसियां पर्याप्त अनाज खरीदने में सक्षम नहीं होतीं। इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार निकाला जाना चाहिए। इसी के साथ कोई ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि किसान इससे परिचित रहे कि कौन सी फसल उगाना लाभदायक है? कई बार किसान यह सोचकर कोई फसल उगाते हैं कि उसकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन व्यापक पैदावार के कारण उसके दाम गिर जाते हैं और इस तरह उन्हें भरपूर पैदावार के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि किसान न केवल इससे चिंतित रहता है कि कहीं उपज कमजोर तो नहीं रह जाएगी, बल्कि इससे भी कि कहीं पैदावार इतनी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी कि उसके दाम गिर जाएं। बेहतर हो कि इस पर गौर किया जाए कि क्या कुछ फसलों की खेती जरूरत से ज्यादा रकबे में कर दी जाती है?

# साहूकारी का दंश

**बहराइच की** ग्राम पंचायत बहदुरिया के विश्राम मजदूर हैं। 20 साल पहले उन्होंने बेटे की शादी के लिए महज आठ हजार रुपये का कर्ज लिया था। बदले में उन्होंने कर्ज देने वाले पूर्व प्रधान के यहां बिना मेहनताना लिए 18 साल तक नौकरी की और करीब 36 हजार रुपये भी धीरे-धीरे करके दे दिए। 22 हजार रुपये का तकादा फिर भी जारी था। थक हारकर 20 मई को विश्राम मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे और व्यथा सुनाई। मुख्यमंत्री के आदेश पर मामला सुलझ गया। विश्राम को न केवल कर्ज से छुटकारा मिला बल्कि पूर्व प्रधान से उन्हें 75000 रुपये भी मिले। समग्रता में बात करें तो विश्राम महज उदाहरण मात्र हैं।

गांवों से लेकर शहरों तक साहूकारों या महाजनों के चंगुल में ऐसे करोड़ों विश्राम फंसे हुए हैं जिन्होंने एक बार यदि कर्ज ले लिया तो पीढ़ियों तक उतरने का नाम नहीं लेता। साहूकारों का बाल तक बांका इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनका कारोबार बिना लिखा पढ़ी के होता है। मतलब यह कि अब ज्यादातर साहूकार रेहन या गिरवी के आधार पर कारोबार करने लगे हैं। ब्याज की दर तो ऊंची रखते ही हैं, ब्याज पर भी स्याज लेने की शर्त जोड़ लेते हैं। हालात ऐसे कर देते हैं कि गरीबों के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। गुलामी, दासता, बंधुआ जैसे शब्द भी इसी व्यवस्था की देन हैं। कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां वेतन दिवस पर साहूकार वेतनभोगी को चैन तक नहीं लेने देते। ऊबकर कर्जदार के आत्महत्या जैसे कदम उठा लेने की घटनाएं भी प्रकाश में आती रहती हैं। सरकारें भले ही बैंकों को कर्ज का दायरा गरीब वर्ग में बढ़ाने का दावा करती हों, पर अव्वल तो उन्हें कर्ज मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो कमीशनखोरी में कट-कटाकर आधी अधूरी रकम ही उनके हाथ में पहुंचती है।

कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां वेतन दिवस पर साहूकार वेतनभोगी को चैन तक नहीं लेने देते

## कह के रहेंगे

माधव जोशी




## जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर सफल रही है?




**आज का सवाल**

क्या कुछ नेताओं द्वारा अनर्गल आरोप लगाने के बाद माफी मांगने से नेताओं की साख घटी है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# रेत की भीत पर खड़ी विपक्षी एकता



**प्रदीप सिंह**

**विपक्ष के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर केवल भाजपा को रोकने के लिए एक होने वालों को मतदाता क्यों चुने?**

सबसे पहले दो बयान देखिए: पहला, 'मैं किराये का मकान खोज रहा हूं। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए दो साल का समय और दिया जाए।' दूसरा, 'मेरी उम्र हो गई है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, किराये का मकान खोजने के लिए दो साल का समय चाहिए।' ये बयान हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने हैं। एक सरकारी बंगले के लिए जो इस तरह गुहार लगा रहे हैं वे केंद्र में नरेंद्र मोदी और भाजपा का विकल्प बनने की बात कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का हाल भी अलग नहीं है। कोर्ट का फैसला आते ही बंगले पर कांशीराम विश्राम स्थल का बोर्ड लग गया। जो एक सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे उनसे किस संघर्ष की उम्मीद की जाए? विडंबना देखिए कि इन्हीं पर विपक्षी एकता का दारोमदार है। कर्नाटक में जो विपक्षी एकता का दृश्य दिखा वह दिल्ली आते-आते बदलने लगा। वैसे थोड़ी खटास तो बेंगलुरु में ही दिखने लगी थी। सोनिया गांधी और मायावती का सखीपन ममता दीदी को रास नहीं आया। उनका गुस्सा उतरा बेंगलुरु की पुलिस कमिश्नर पर। बेंगलुरु में जो भाजपा को रोकने के लिए त्याग की बात कर रहे थे उनमें से किसी को सरकारी बंगले की चिंता सता रही है तो किसी को सम्मानजनक सीटों की। लखनऊ पहुंचते ही मायावती के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटें न मिलीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सम्मानजनक की परिभाषा तो मायावती ही तय करेंगी। सीताराम येचुरी ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले किसी तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। नवीन पटनायक तो बेंगलुरु गए भी नहीं। इस विपक्षी एकता की बारात का दूल्हा बनने का इरादा रखने वाले राहुल गांधी इन सारे झमेलों से दूर विदेश निकल लिए, जबकि कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद वह कैलास मानसरोवर जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अपनी सरकार के चार साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कांग्रेस इसे विश्वासघात के रूप में मना रही है। पिछले चार साल से नकारात्मक एजेंडा कांग्रेस का स्थायी भाव बन गया है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ अन्य विपक्षी दल मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फासिस्ट, जनतंत्र विरोधी और न जाने क्या-क्या कहते रहते हैं, लेकिन यही सब पश्चिम बंगाल में जनतंत्र की सरेआम हत्या पर चुप्पी साधे रहते हैं। यह एक तथ्य है कि जिन विपक्षी दलों ने चंद दिन पहले हुए उपचुनावों में महज एक फीसदी वोटिंग मशीनों में खराबी आने पर चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने से गुरेज नहीं किया उन्होंने पश्चिम बंगाल में मतपत्र और मतपेटियां लूटे जाने पर कुछ नहीं कहा। यह दोहरा रवैया ही विपक्ष की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना देता है। कांग्रेस इससे बेपरवाह है कि वह जितना मोदी और भाजपा पर हमला कर रही है उतना ही उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है।



अवधेश राजपूत

कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि भाजपा ने अपने सामाजिक आधार की रणनीति ही बदल दी है। मध्य वर्ग को उसने नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन अब वह उसकी प्राथमिकता नहीं है। उसका सारा जोर अनुसूचित जाति/जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग पर है। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ने के बावजूद सरकार कर घटाने को तैयार नहीं है। उसे यह पता है कि इस विपक्ष में इतनी ताकत नहीं कि वह इस मुद्दे पर कोई आंदोलन खड़ा कर सके। इस मुद्दे पर विपक्ष का सारा विरोध बयानों तक ही सीमित है। तेल के दाम पर आम लोगों में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया न होने का एक कारण यह भी है कि चार साल पहले भी लोग सत्तर रुपये से ज्यादा एक लीटर पेट्रोल के लिए दे चुके हैं। वह भी ऐसे समय में जब महंगाई दहाई में थी।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा का सारा जोर समाज के वंचित वर्ग को पार्टी से जोड़ने पर है। यह वर्ग लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आया। उसी को स्थायी रूप से पार्टी से जोड़ने के लिए सरकार और पार्टी संगठन जी-जान से लगा हुआ है। कांग्रेस यह सवाल पूछकर संतुष्ट है कि अच्छे दिन आए क्या? वह शायद यह समझ रही है कि मोदी सरकार को सूट बूट वाली और उद्योगपतियों की सरकार बताकर उसने मैदान मार लिया है। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गरीब के घर में उज्ज्वला से रसोई गैस, स्वच्छता से शौचालय, सौभाग्य से बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला उसके तो अच्छे दिन आ ही गए। मुद्रा योजना को लेकर कांग्रेस आंकड़े गिना रही है, लेकिन जिन छोटे व्यावसायियों को इससे लाभ मिला है उनके तो अच्छे दिन आए ही। जनधन और डीबीटी (डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से मनरेगा और दूसरी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे जिनके बैंक खाते में पहुंचा उनके लिए तो अच्छे दिन आ ही गए। प्रधानमंत्री एक-एक करके इन सभी लाभार्थी वर्गों से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। खेती-किसानी की हालत सुधारने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है जहां यह बहुत कुछ भी नाकाफी साबित हो रहा है।

संभावित विपक्षी एकता यदि किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है तो वह उत्तर प्रदेश है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मिलने से अंकगणित के हिसाब से अजेय गठबंधन बनता नजर आता है। वैसे यह प्रयोग 1993 में भी हो चुका है। उस समय कांशीराम दलितों के नेता थे और मुलायम सिंह पिछड़ों और मुसलमानों के। फिर भी दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं ला पाए थे। आज मायावती दलितों के बजाय सिर्फ जाटवों की नेता रह गई हैं तो अखिलेश सिर्फ यादवों और मुसलमानों के। जो लोग गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के आधार पर इस गठबंधन की ताकत आंक रहे हैं उन्हें 2019 में झटका लग सकता है, क्योंकि उस समय इस गठबंधन के सामने मोदी होंगे और जमीन पर अमित शाह की टीम।

कोई भी विपक्षी एकता किसी वैचारिक कार्यक्रम, संगठन की शक्ति और नेतृत्व के बिना निष्प्रभावी है। विपक्ष के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए एक होने वालों को आखिर मतदाता क्यों चुने? सुबह-शाम मोदी को गाली देने और उन्हें नाकारा बताने के बावजूद विपक्षी दल प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को कम नहीं कर पाए हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद एक बार फिर राजनीतिक परिदृश्य से गायब होकर राहुल गांधी इस धारणा को पुष्ट ही कर कर रहे हैं कि वह एक गंभीर राजनेता नहीं हैं। उनके विदेश चले जाने से कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है-उसी सरकार का जिसे बनाने के लिए उनकी पार्टी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची थी। जीवन की तरह राजनीति में भी कोई शॉर्टकट नहीं होता।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

# सच्चे जनप्रतिनिधियों की तलाश



**जगमोहन सिंह राजपूत**

**आखिर वह दिन कब आएगा जब जन सेवा के लिए त्याग करने वाले लोग ही जनप्रतिनिधि बनेंगे**

इस समय तमाम लोग उस सबको सामान्य सा मानने लगे हैं जिन्हें वे आजादी के वक्त अप्रत्याशित, असामाजिक, अस्वीकार्य या तिरस्कार योग्य मानते थे। गांधीजी ने 1922 में एक पत्र में लिखा था कि स्वराज आने से देशवासियों को कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि चार चीजें उन पर भारी पड़ेंगी। इनमें चुनावों के दोष, अन्याय, प्रशासन का बोझ और अमीरों के अत्याचार को उन्होंने शामिल किया था। 1922 के लिहाज से मुझे इन चारों में चुनावों के दोष को शामिल करना समझ से परे लगता था, लेकिन गांधीजी ने ब्रिटिश चुनावों का गहरा अध्ययन किया था। वह भारतीयों के मानस को भी भली तरह समझते थे। भारत के पहले आम चुनाव को जिन्होंने देखा हो वे ही आज तक आए परिवर्तन को समझने में अच्छे से सक्षम हो सकते हैं। ऐसे लोगों का यही कहना होता है, 'इस परिवर्तन की हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी।' कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलों को गैर संवैधानिक करार दिया। आखिर यह प्रजातंत्र का कौन सिद्धांत है जिसमें सरकार अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनपर्यंत सरकारी बंगले देना जरूरी समझती हो? जब जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग समाज स्वीकार कर ले तो भारतीय प्रजातंत्र के प्रशंसकों का सिर भी शर्म से झुकेगा। आखिर उस विधायिका का सम्मान कहां पहुंचेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अमर्यादित प्रस्ताव पास कर देती हो ताकि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले बचे रहें? कुछ वर्ष पहले मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी एक खबर पढ़ी जिसमें एक याचिका को निरस्त किया गया था। एक नेता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि अदालती फैसले के चलते उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी, लिहाजा उन्हें भी 'भूतपूर्व मुख्यमंत्री' माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मेरी अपेक्षा थी कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री एक सुर से यह घोषणा करेंगे कि वे कोर्ट के निर्णय का सिद्धांत रूप में स्वागत करते हैं और अपना बंगला छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार केवल राजनाथ सिंह ने अपना बंगला छोड़ा है और कल्याण सिंह छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शेष पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह बंगला छोड़ने से बचना चाहते हैं उससे राजनीति का चेहरा ही स्पष्ट होता है। जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हों, जहां लाखों लोगों को भरपेट भोजन न उपलब्ध हो वहां विधायकों और सांसदों को हर चुनाव जीतने पर एक नई पेंशन मिलती हो और वे सभी को साथ-साथ लेते रहने को अधिकृत हों तो इससे बड़ा अन्याय या सत्ता का दुरुपयोग और क्या हो सकता है? क्या किसी अन्य श्रेणी के पेंशनभोगी के लिए यह सुविधा




उपलब्ध है? तमाम विधायक और सांसद वे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी संपत्ति एक कार्यकाल में ही असीमित ढंग से बढ़ सकती है। वे यदि केवल कुछ दिन यानी केवल एक दिन के लिए भी जन प्रतिनिधि बने तो जीवनपर्यंत पेंशन के हकदार हो जाते हैं? इतना प्रगतिशील कोई दूसरा देश मुझे तो खोज करने पर भी नहीं मिला।

लियो टॉलस्टॉय की एक मशहूर कहानी है कि एक मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए? एक व्यक्ति को जब यह अवसर दिया गया कि दिन भर में वह एक घोड़े पर बैठकर जितनी जमीन का चक्कर लगा लेगा वह मुफ्त में उसकी हो जाएगी। इस कवायद में उसने इतनी ऊर्जा लगा दी कि वह अंतिम समय में निढाल होकर गिर गया। तब उसे लगा कि जमीन तो केवल ताबूत भर के लिए चाहिए। किंवदंती है कि सिकंदर ने भी अंतिम समय में कहा था कि उसके खाली हाथ ताबूत से बाहर रखे जाएं ताकि वे लोगों को बता सकें कि इतना बड़ा सम्राट भी साथ में कुछ न ले जा सका।

जब गांधी जी ने यह कहा था कि 'प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो संसाधन हैं, मगर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं हैं' तब शायद उनके मन में भी देश के भविष्य की चिंता ही बलवती रही होगी। यह देश स्वतंत्रता के बाद अधिकांश वर्षों में उन लोगों की सत्ता में रहा है जो स्वयं को गांधी और उनके विचारों एवं सिद्धांतों का वारिस होने की बात कहते रहे हैं। पिछले 70 साल में अधिकांश प्रतिनिधि तो इसी श्रेणी से आए हैं। सांसद और विधायक ही देश के कानून निर्माता भी हैं। अपनी 'तनख्वाह और भत्ते' भी वे स्वयं ही निर्धारित करने लगे। निर्वाचित होने के तुरंत बाद उन्हें घर चाहिए और अपना घर बनाने के लिए ऋण भी उदार शर्तों पर चाहिए। वेतन भत्ते के अतिरिक्त पेंशन, टेलीफोन, मोबाइल और भी न जाने क्या-क्या चाहिए। जनता और नेता का संबंध अब कुछ ऐसा हो गया है कि 'मैंने तुम्हारी सेवा की घोषणा की है, मुझे चुनकर तुमने उसे स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हें मेरी और मेरे परिवार की सेवा करनी है।' क्या यह अद्भुत तथ्य नहीं कि कई नेता सत्ता में रहकर कंगाल से अरबपति हो जाते हैं। उनके बच्चे बालिग होने के पहले ही करोड़पति हो जाते हैं। वे मॉल बनवाते हैं, फार्म हॉउस के मालिक बन जाते हैं और उनकी कंपनियां जमकर लाभांश कमाती हैं। यदि कोई कार्रवाई शुरू होती भी है तो उसे तुरंत बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई घोषित कर दिया जाता है।

स्कूलों में यही पढ़ाया जाता रहा है कि जनप्रतिनिधि का चरित्र अनुकरणीय होता है। जैसे पहले सिखाया जाता था कि 'महाजनो येन गतः सा पंथाः' यानी उस मार्ग पर चलो जिस पर बड़े और महान लोग चले हों। इस काल-खंड में जो चमक-दमक, सत्ता की हनक, कार-काफिले, प्रशंसकों के हुजूम जन-प्रतिनिधियों को उपलब्ध हैं वे किस युवा को प्रभावित नहीं करेंगे? किसके भीतर शीघ्रता से अधिक से अधिक धन प्राप्ति के प्रयास करने का जज्बा हिलोरे नहीं लेगा? वे यह भी तो जानते हैं कि कितने ही मुकदमे जन प्रतिनिधियों के नाम के आगे लगे हों, उनसे उनकी और उनके परिवार की तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ता।

चुनाव होते रहेंगे, परिणाम आते रहेंगे, जनता के पैसे पर आश्रित भूतपूर्व नेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन वह दिन कब आएगा जब जनता की सेवा के लिए त्याग करने वाले ही जन प्रतिनिधि बनेंगे। जब सिद्धांतविहीन राजनीति को पाप माना जाएगा और जनता ऐसे लोगों का तिरस्कार करेगी? अंततः ऐसा ही होना होगा, क्योंकि देश तभी बचेगा।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### सिद्धांत

सिद्धांत शब्द का संधि विच्छेद है-सिद्ध+अंत। सार्वजनिक व सार्वभौमिक कल्याण कामना से जो भाव-विचार सिद्ध हों या जिस भाव-विचार की सिद्धि लोक कल्याण के लिए कार्यरूप में हो, वही सिद्धांत कहलाता है। इस विचार में यदि वास्तव में सर्व सुख-शांति की शक्ति है और व्यावहारिक बनने पर यह विचार अपनी वैचारिक श्रेष्ठता बनाए रख सकता है तो यह सिद्धांत में बदल जाता है। इसी प्रकार के अनेक विचार अपनी-अपनी वैचारिकता और व्यावहारिकता के सामंजस्य से मानव उत्थान में जो योगदान देते हैं, उसी के आधार पर वे सिद्धांत बनते रहते हैं। चूंकि मानवीय जीवन चाहे-अनचाहे उत्तरोत्तर कल्याण, विकास की ही कामना रखता है। इसीलिए सार्वभौमिक कल्याणकारी विचार और व्यवहार के फलस्वरूप जो सामाजिक सूचना प्रसारित होती है, वह धीरे-धीरे सर्वस्वीकार्य हो जाती है। इस तरह एक सिद्धांत उत्पन्न होता है। समझदार और प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सिद्धांत अवश्य होते हैं।

सिद्धांत से तात्पर्य दैनिक वस्तुओं के उपभोग के नियम में बंधने से नहीं है। मनुष्य के भाव-विचार वास्तविक संसार के विषयों से अलग होकर व्यक्तिगत चेतना से संचालित होने चाहिए। ऐसा होने पर विषयों के प्रति आत्मिक दृष्टिकोण बनने लगता है। विषय-विकार मिटने लगते हैं। इसके बाद दुनियावी पूर्वाग्रह और भावी आग्रह एक नई विचार-छलनी से छलने लगते हैं और इसमें से निकलकर जो नव विचार व्यक्ति को उचित लगते हैं, वे सिद्धांतों का रूप ग्रहण करते हैं। प्रत्येक विचार मौलिकता, परोपकार की भावना से पोषित होना चाहिए। इस उपक्रम से सैद्धांतिक वातावरण बनने लगता है। मनुष्य अपने इष्टतम ज्ञान को पहचाने और उसका उपयुक्त प्रयोग करे। यह तभी संभव है, जब उसके ज्ञान के सिद्धांत निर्धारित हों। इस दुनिया में सभी का जीवन निर्धारित समय तक ही है। मृत्यु के बाद लोग सशरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। यदि कोई अपनी मृत्यु के बाद इस संसार में कुछ छोड़ जाता है तो वे उसके मौलिक व मानवीय सिद्धांत ही होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर आसानी से समझा जा सकता है कि जीवन के बाद भी हमारी पहचान हमारे सकारात्मक और जीवन से संबंधित सिद्धांतों के बल पर ही हो सकती है।

विकेश कुमार बडोला

## पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

### भारत-इंडोनेशिया संबंधों का आधार

इंडोनेशिया से दोस्ती बढ़ाने का वक्त शीर्षक से लेख प्रकाशित गुरजीत सिंह का लेख कुछ अधूरा-अधूरा सा है। इसमें वर्तमान समय में जो आर्थिक कारक दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती दे सकते हैं, उनकी चर्चा तो पर्याप्त है, किंतु जो हिंदू-बौद्ध संस्कृति हजारों साल से दोनों राष्ट्रों के मध्य सेतु बनी रही है, उसको बहुत ही गौण स्थान दिया गया है। चीन ने एक दशक पूर्व अपने हेनान प्रांत में विश्व की सबसे ऊंची (500 फुट) बुद्ध-प्रतिमा का निर्माण किया, ताकि दक्षिण-पूर्व एवं पूर्वी एशियाई बौद्ध देशों से रिश्ते मधुर बनाने में सहायता मिले। राष्ट्रों की मित्रताएं केवल शुष्क आर्थिक-राजनीतिक कारकों पर नहीं टिकती हैं, भावनात्मक तथा सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंडोनेशिया ने 2012 में भारत सरकार से कुछ योग-शिक्षक मांगे थे, किंतु मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी। इस बात का दुःख जकार्ता को निश्चित रूप से हुआ होगा। इंडोनेशिया ने अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलनों का आयोजन किया है। वहां प्रंबनन मंदिर के प्रांगण में 1962 से प्रतिदिन रामकथा का मंचन किया जाता है। वहां स्वतंत्रता दिवस परेड में सैकड़ों हनुमान-वेशधारी युवा सम्मिलित होते हैं। रामायण वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इन सांझी सांस्कृतिक विरासत को आधार बनाकर, सम्मान देकर ही दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। कहने की जरूरत नहीं, मोदी इस फन में माहिर हैं।

अजय मित्तल, मेरठ

### पेट्रोल के दाम

16वें दिन तेजी से बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों पर एक पैसा गिरकर बमुश्किल ब्रेक लगा है। अब जल्द ही राहत की सांस ले लेनी चाहिए, वरना पता नहीं कब ब्रेक के फिर भाव बढ़ जाएं और बढ़े भाव सुनकर श्वांस जहां की तहां फिर अटक जाए...।

mahesh_nenava@yahoo.com

### शानदार जीत

आइपीएल के 11वें संस्करण के सभी मैच बेहद रोमांचक रहे और दो साल बाद वापसी कर रही चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने अंततः आइपीएल का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया। इससे पहले मुंबई इंडियंस की टीम ही इस खिताब को तीन दफा जीतने में कामयाब रही है। चेन्नई की टीम सात बार आइपीएल के फाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र टीम है। चेन्नई की टीम को उम्रदराज खिलाडियों की टीम बताकर मजाक बनाया गया था, लेकिन इस जीत ने उन सभी बातों को खोखला साबित कर दिया। हमें धोनी और उनकी टीम पर गर्व है।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

### विधायकों को धमकी

पिछले लगभग दस दिन से उत्तर प्रदेश में मुख्यतः भाजपा के विधायकों को विदेशी नंबरों के मोबाइल फोनों से फिरौती मांगने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे 10-10 लाख रुपयों की मांग की जा रही है। यह धमकी भरे संदेश पाकिस्तान, दुबई व अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों से आ रहे हैं। ऐसा करने वाले आतंकी भी हो सकते हैं? सुरक्षा एजेंसियों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

विनोद कुमार सर्वोदय, गाजियाबाद

### असंवैधानिक कार्य नहीं

कर्नाटक में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, इसीलिए राज्यपाल ने उसे सरकार बनाने का न्यौता दिया था। इस आधार पर राज्यपाल को हटाने की मांग अनुचित है। राज्यपाल ने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया। उन्होंने वहीं किया जो संविधान में दर्ज है।

हरगोपाल तनेजा, सोनीपत

### प्रणव मुखर्जी क्यों नहीं ?

पूर्व राष्ट्रपति डा. प्रणब मुखर्जी इस समय चर्चा में हैं। इसका कारण है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर 7 जून को संघ मुख्यालय नागपुर जा रहे हैं। वहां वे संघ के तृतीय वर्ष के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। जो लोग संघ को जानते और समझते हैं उनके लिए न तो यह आश्चर्यजनक घटना है और न ही नई बात है। उनके लिए यह सामान्य बात है, क्योंकि संघ अपने कार्यक्रमों में समाज सेवा में सक्रिय और प्रमुख लोगों को अतिथि के रूप में बुलाता रहा है। इस बार संघ ने डा. प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित किया है। इसी तरह 1934 में तो पूज्य महात्मा गांधी स्वयं वर्धा में संघ के शिविर में आए थे। उन्होंने संघ के अनुशासन, सादगी और समरसता की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि संघ एक सुसंगठित, अनुशासित संस्था है। यह उल्लेख 'सम्पूर्ण गांधी वांग्मय' खण्ड 89, पृष्ठ सं. 215-217 में है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन, बाबू जयप्रकाश नारायण भी संघ के आमंत्रण पर आए हैं और उन्होंने संघ की प्रशंसा की है। 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय संघ के स्वयंसेवकों की सेवा से प्रभावित होकर ही 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संघ को आमंत्रित किया था और 3 हजार स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया था। संघ की राष्ट्र प्रथम भावना के कारण ही 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने संघ के सरसंघचालक 'श्री गुरूजी को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया था और वे गए भी थे। 1963 में स्वामी विवेकानंद जन्मशती के अवसर पर कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक निर्माण के समय भी संघ को सभी राजनैतिक दलों और समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला था।

chanderv96299@gmail.com

## ट्वीट-ट्वीट

सरल ढंग से समझिए कि जैसे आपके स्मार्टफोन हैंग होने का मतलब उसका हैक होना नहीं होता, वैसे ही ईवीएम खराब होने का मतलब उससे टैंपरिंग होना नहीं होता।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

खराब प्रदर्शन के बावजूद सरकारी बैंक वेतन बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर आमादा हैं। काश सभी दल मिलकर इन बैंक कर्मियों के खराब रवैये का हल निकाल सकें।

सुनील जैन@thesuniljain



अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी राजपत्रित अधिकारी हैं। उनकी पांच और बहनें भी ऐसे ही पद पर हैं। बेटी सीबीएसई टॉपर है, लेकिन दूसरों के बच्चों को वह जिहाद में शामिल होने की तालीम देते हैं।

रतन शारदा@RatanSharda55

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के वर्चस्व के बजाय उदारवादी ढांचे के लिए आसियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि पीएम मोदी का इंडोनेशिया सहित अन्य देशों का दौरा इस क्षेत्र में भारत के लिए बेहतर संभावनाएं बनाएगा।

जयवीर शेरगिल@JaiveerShergill

इस उदारता पर मेरा दिल बेहद द्रवित है। वे चाहते तो ईंधन की दरों में आधे पैसे की कटौती कर सकते थे, लेकिन दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने पूरे एक पैसे की कटौती की। पूरा देश इसके लिए कृतज्ञ है।

सुहेल सेठ@suhelseth

## जनपथ

नंबर लाए इस तरह नौनिहाल इस बार,
पढ़ना-लिखना स्वयं का लगता है बेकार।
लगता है बेकार रात भर किया रिवीजन,
जब आया परिणाम रहे बस सेकेंड डिवीजन।
नौनिहाल शाबाश ! चूमिए जमकर अम्बर,
ला करके हर बार बाप से ज्यादा नंबर।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 316